उत्तरी क्षेत्र का औद्योगिक विकास

688. **लाला लाजपत राय**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)नई औद्योगिक नीति को लागू किये जाने के उपरान्त उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में किस हद तक औद्योगिक विकास हुआ हैं;

(ख) 31 दिसम्बर,1998 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास दर की तुलना में इन राज्यों में कुल कितना निवेश किया गया हैं;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर क्षेत्र में राज्यों,विशेषकर पंजाब में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की हैं;और

(घ) यदि हां,तो घोषित नीति की मुख्य रूपरेखा क्या हैं?

उद्योग मंत्री (**श्री सिकन्दर बख्त**): (क) और (ख) अगस्त 1991 से दिसम्बर,1998 की अवधि के लिए अखिल भारतीय निवेश की तुलना में उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में प्रस्तावित निवेश तुलनात्मक स्थिति दर्शाने वाला विवरण सलग्र हैं। (**नीचे देखिए**) 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार इन राज्यों में किये गये वास्तविक निवेशके आंकड़े इस मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय उद्योगों को गतिमान तथा विश्व में प्रतियोगी बनाये रखने के लिए,सरकार ने घरेलू तथा विदेशी दोनों निवशों की अनुमति के लिए नियमों को सरल बनाने की दिशा में अनेक उपाय किये हैं । छः उद्योगों की एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर,जिनके लिए औद्योगिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं,अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पास एक विकास केन्द्र योजना हैं जिसके तहत बिजली,पानी दूरसंचार,बैंकिग जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है जैसे कि पंजाब राज्य सरकार जिसे दो विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं जिनके लिए प्रत्येक केन्द्र हेतु 1000 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई हैं । इसके अलावा परिवहन राजसहायता योजना,1971 भी पर्वतीय,दूरस्थ और क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है,जो कि पात्र क्षेत्रों के लिए लागू हैं और इस योजना में सभी औद्योगिक इकाइयां,चाहेवह सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र की हों,उनके आधार पर ध्यान दिये बिना इस योजना में शामिल हैं परन्तु इसमें बागवानी,रिफाइनरी तथा विद्युत जनित्रण इकाइयां शामिल नहीं है।

विवरण

अगस्त,1991 से दिसम्बर,1998 की अवधि में अखिल भारतीय औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के बारे में उत्तरी राज्यों में प्रस्तावित निवेश को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण –पत्र

क्रम .सं.	राज्यों का नाम	औ.उ. शा.	प्रस्तावित निवेश(करोड़ रूपये थे)	आशय पत्र **	प्रस्तावित निवेश(करोड़ रूपये में)	औ.उ.शा आशय पत्र	कुल प्रस्तावित निवेश(करोड़ रूपये में)
1.	उत्तर प्रदेश	3470	61326	343	9828	3821	71154
2.	हरियाणा	2227	23047	178	4045	2405	27092
3.	पंजाब	1704	21111	136	4446	1840	25557
4.	हिमाचल प्रदेश	347	7649	32	476	379	8125
5.	जम्मू और कश्मीर	66	437	4	66	70	503
6.	दिल्ली	449	6379	17	30	466	6409
	योग	8271	119949	710	18891	8981	13884
	अखिल भारतीय	35153	653480	3232	103846	38385	757326

*औ.उ.शा.-औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन

** आ.पत्र- आशय-पत्र